नईदुनिया

ट्रम्प प्रशासन में मस्क और रामास्वामी की भी होगी बड़ी भूमिका

वाशिंगटन

संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी बड़ी भूमिका में होंगे। ट्रम्प के चुनाव अभियान का हिस्सा रहे इन दोनों अरबपति समर्थकों को नौकरशाहों से ऊपर रखा जाएगा।

ट्रम्प को उम्मीद है कि इससे संघीय नौकरशाही में आमूल-चूल परिवर्तन लाया जा सकेगा।

खबर के अनुसार, इन अरबपति समर्थकों को सरकारी दक्षता विभाग में रखा जाएगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि सरकारी दक्षता विभाग 4 जुलाई, 2026 तक संपूर्ण संघीय नौकरशाही में बड़ा परिवर्तन लाएगा। दोनों इस विभाग का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि यह इस युग का मैनहट्टन प्रोजेक्ट होगा।

यह प्रोजेक्ट 4 जुलाई, 2026 तक संघीय नौकरशाही में विकसित एजेंसियों में बड़ी कटौती और नई दक्षताओं के साथ पूरी सरकार में कठोर बदलाव लाएगा।

ट्रम्प ने एक बयान में कहा अधिक दक्षता और कम नौकरशाही के साथ एक छोटी सरकार, स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के लिए सबसे अच्छा उपहार होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह इसमें सफल होंगे।

उल्लेखनीय है कि मस्क ने चुनाव से पहले कहा था कि वह निर्वाचित राष्ट्रपति को संघीय बजट से दो ट्रिलियन डॉलर की कटौती करने में मदद करेंगे।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में मस्क को संघीय एजेंसियों के कम से कम 20 अलग-अलग जांच या मुकदमों का सामना करना पड़ा है। ट्रम्प के बयान में कहा गया कि मस्क का विभाग सरकार को बाहर से सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

ट्रम्प ने उम्मीद जताई है कि एलन मस्क और विवेक संघीय नौकरशाही में दक्षता को ध्यान में रखते हुए बदलाव करेंगे और साथ ही सभी अमेरिकियों के लिए जीवन को बेहतर बनाएंगे। महत्वपूर्ण यह होगा कि हम अपने वार्षिक 6.5 ट्रिलियन डॉलर के सरकारी खर्च में होने वाली बड़ी बर्बादी को रोकेंगे।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग की प्रमुख होंगी दक्षिण डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग की सर्वेसर्वा दक्षिण डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम होंगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को उन्हें होमलैंड सुरक्षा विभाग को चलाने के लिए चुना। अब क्रिस्टी नोएम पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प की आव्रजन नीति को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी होगी। खबर के मुताबिक नोएम अमेरिकी आव्रजन, सीमा शुल्क प्रवर्तन, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा सहित आव्रजन कानूनों को लागू करने वाली एजेंसियों की भी प्रभारी होंगी। इस चुनाव में ट्रम्प ने नागरिकों से आव्रजन नीति को लेकर बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा था कि जीत होने पर सीमा पर आक्रामक तरीके से पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। साथ ही पूरे देश में व्यापक पैमाने पर निर्वासन अभियान भी चलाया जाएगा। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर एक बयान में नोएम को सीमा सुरक्षा पर बहुत मजबूत कहा। उन्होंने जिक्र किया कि क्रिस्टी नोएम ने गवर्नर के रूप में टेक्सास मैक्सिको सीमा पर नेशनल गार्ड सैनिकों को भेजा था। इस बीच नोएम ने सोशल मीडिया बयान में सीमा को सुरक्षित करने और अमेरिकी समुदायों को सुरक्षा बहाल करने का वादा किया ताकि परिवारों को फिर से अमेरिकी सपने को आगे बढ़ाने का अवसर मिले।

नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा बैठक 16-17 नवंबर को, शामिल होंगे एसएसबी के महानिदेशक

काठमांडू। नेपाल और भारत के सीमा सुरक्षा अधिकारियों की शीर्ष बैठक 16 और 17 नवंबर को नेपाल में होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के डायरेक्टर जनरल नेपाल आ रहे हैं। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बल के शीर्ष अधिकारियों के बीच हर वर्ष इस तरह की बैठक बारी-बारी से दिल्ली और काठमांडू में होती है। नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल के प्रमुख आईजीपी राजू अर्याल के निमंत्रण पर एसएसबी के डीजी अमृत मोहन प्रसाद 15 नवंबर से तीन दिन के लिए काठमांडू आने वाले हैं। आईजीपी अर्याल ने बताया कि दोनों देशों के बीच होने वाली वार्षिक सीमा सुरक्षा बैठक पिछले वर्ष नई दिल्ली में हुई थी, इसलिए इस बार बैठक का आयोजन काठमांडू में किया जा रहा है। सशस्त्र प्रहरी बल के आईजीपी ने बताया कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा सीमा पार अपराध का नियंत्रण करने के उपायों के बारे में है। साथ ही ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने में दोनों देशों के सीमा सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि खुली सीमा होने के कारण तीसरे देश के नागरिकों का नेपाल से भारत और भारत से नेपाल में प्रवेश करने से रोकने के लिए भी संयुक्त गश्त को बढ़ाने पर भी बैठक में चर्चा होगी।

पाकिस्तान में हो रहे चीनियों पर हमले से भड़का चीन- अब खुद करेगा सुरक्षा

बीजिंग। पड़ोसी देश पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बार-बार हो रहे हमलों के बाद अब चीन खुद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान में हो रहे हमलों को रोकने में पाकिस्तानी सरकार और सेना असफल साबित हो रहे हैं, जिससे बीजिंग का धैर्य अब जवाब दे रहा है। हाल के घटनाक्रम में कराची में हुए कार बम विस्फोट में दो चीनी इंजीनियरों की मौत हुई, जिससे चीन में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। इस हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान पर अपने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का प्रस्ताव दिया है ताकि चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि पाकिस्तान में चीन का बड़ा निवेश है, विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में, जिन पर आतंकियों की भी नजर है। सूत्रों के अनुसार, बीजिंग ने इस्लामाबाद को एक लिखित प्रस्ताव भी भेजा है, जिसमें अपनी सुरक्षा टीम को पाकिस्तान में तैनात करने की अनुमति मांगी है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में हैं और अभी तक उन्होंने इसे मंजूरी नहीं दी है।

श्रीलंका में संसदीय चुनाव की तैयारी पूरी, आज सुबह सात बजे से होगा मतदान

कोलंबो

श्रीलंका में संसदीय चुनाव-2024 की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। इसमें तरजीही मतों के जरिए 196 प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय सूची से 29 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा, ताकि नई 10वीं संसद के लिए 225 प्रतिनिधियों का चयन किया जा सके। इस बार 17.1 मिलियन मतदाता 22 बहु-सीट निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार करने के पात्र हैं। नई संसद की पहली बैठक 21 नवंबर को आहूत की जा सकती है। राजधानी कोलंबो स्थित डीएस सेनानायके कॉलेज से आज मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा में मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया।

खबर के अनुसार श्रीलंका के चुनाव आयोग ने परिणाम देखने के लिए सार्वजनिक स्क्रीनिंग के प्रदर्शन और भीड़ के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोग ने नागरिकों से चुनाव परिणाम घोषित होने की अवधि के दौरान घर पर रहने का आग्रह किया गया है। आयोग ने कहा है कि घरों के अंदर ही रिजल्ट देखें।

आयोग के अध्यक्ष आरएमएएल रथनायके ने कहा कि चुनाव परिणामों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग के दौरान होने वाले झगड़े और हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने प्रबंध किए हैं। लोगों को मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों के पास रहने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जिन्हें आधिकारिक मतदान कार्ड नहीं मिले हैं, वो अपने क्षेत्रों के डाकघरों से उन्हें प्राप्त कर लें। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से भी मतदान कार्ड के प्रिंट लिए जा सकते हैं। मताधिकार के लिए कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है और मतदाता 2024 के मतदान रजिस्टर में अपने विवरण को सत्यापित करने के लिए पहचान का वैध प्रमाण प्रस्तुत करके अपना वोट डाल सकते हैं।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के दिन डाक मतों की गिनती शाम 4.15 बजे शुरू होगी और नियमित वोटों की गिनती शाम 7.15 बजे के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। मतगणना प्रक्रिया पहले प्रत्येक बॉक्स में मतपत्रों की गिनती के साथ आयोजित की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक राजनीतिक दल या स्वतंत्र समूह के वोटों की गिनती की जाएगी, फिर प्रत्येक को आवंटित संसदीय सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी और अंत

में व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए अधिमान्य वोटों की गिनती की जाएगी। आयोग ने लोगों को मतपत्रों या मतदान प्रक्रिया की तस्वीरें या वीडियो लेने से परहेज करने की सलाह दी है।

मीडिया के लिए अधिकृत पुलिस प्रवक्ता निहाल थल्दुवा ने कहा कि चुनाव में मोबाइल गश्त के लिए एक नए इंटरनेट एप्लिकेशन का भी उपयोग किया जाएगा। संसदीय चुनाव के अवलोकन में 20 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। संसदीय चुनाव के कारण देश के सभी स्कूल 13 और 14 नवंबर को बंद रहेंगे। डेली मिरर अखबार के अनुसार आयोग के अध्यक्ष आरएमएएल रथनायके ने कहा कि मतगणना पूरी होने के बाद आधिकारिक नतीजे मीडिया को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने मीडिया आउटलेट्स से अनौपचारिक चुनाव परिणाम जारी करने से परहेज करने का आग्रह किया है।

हूती ने अमेरिका के लिंकन और डेस्ट्रायर पर किया ड्रोन अटैक

वॉशिंगटन। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और दो डेस्ट्रायर को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को एयर एंड मिसाइल यूनिट ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए दो स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया। एक ऑपरेशन अरब सागर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, तो दूसरी लाल सागर में मौजूद दो डेस्ट्रायर वॉरशिप पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के अंजाम दिया। अमेरीक सेंट्रल कमॉड की तरफ से अभी फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। कुछ घंटे पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर से कई एयरक्राफ्ट हूती के खिलाफ लान्च किए गए थे। उधर हूती विद्रोहियों ने एक बयान में कहा कि यह कदम अमेरिकी हमलों के जवाब में उठाया गया है। ये हमले रात में हुए थे। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गाजा और लेबनान के लोगों के समर्थन में की गई है। बयान में कहा गया है कि समूह ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 'अपने मकसद को सफलतापूर्वक हासिल किया'। बयान में कहा गया है कि लाल सागर में तैनात दो अमेरिकी विध्वंसकों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हूतियों ने कहा कि यह अभियान आठ घंटे तक चला।

अमेरिका के नए रक्षा सचिव होंगे फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेगसेथ, ट्रंप ने की घोषणा

वाशिंगटन

संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले रक्षा सचिव फॉक्स न्यूज के मशहूर होस्ट पीट हेगसेथ होंगे। इराक और अफगानिस्तान युद्ध पर पीट हेगसेथ के विश्लेषण चर्चा में रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को उन्हें अपना अगला रक्षा सचिव चुना। पीट अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पेंटागन और 1.3 मिलियन सैनिकों का नेतृत्व करेंगे।

खबर में कहा गया कि हेगसेथ की पसंद पारंपरिक रक्षा सचिव के मानदंडों से बाहर थी। वह ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके समर्पित समर्थक रहे हैं। पीट हेगसेथ ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ अपनी बातचीत में विदेश से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की कोशिश के ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को अपनाया।

ट्रंप ने अगले रक्षा सचिव के रूप में हेगसेथ के नाम की घोषणा करते हुए उनके युद्ध अनुभव और अमेरिकी सेना के समर्थन की प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा कि पीट सख्त, चतुर और अमेरिका फर्स्ट में सच्चा विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। पीट के नेतृत्व में अमेरिकी सेना फिर से महान होगी।

हेससेथ 2014 में फॉक्स न्यूज के नेटवर्क में शामिल हुए और वर्षों तक फॉक्स के नए साल के कवरेज के मेजबान रहे हैं। मिनेसोटा के मूल निवासी हेगसेथ प्रिंसटन विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। रूढ़िवादी पत्रिका द प्रिंसटन टोरी के प्रकाशक रहे हैं। फॉक्स न्यूज के अनुसार, उन्होंने हार्वर्ड केनेडी स्कूल से सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

हेगसेथ की जून में प्रकाशित पुस्तक द वॉर ऑन वॉरियर्स-बिहाइंड द ब्रिट्रेयल ऑफ द मेन हू कीप अस फ्री बेस्ट सेलर रही है। अपने बयान में ट्रंप ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है।

पाकिस्तान में 5.3 तीव्रता का भूकंप पेशावर से इस्लामाबाद तक हिली धरती

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के कई शहरों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से डरे लोग इमारतें खाली कर बाहर खुले में निकल गए। भूकंप के झटके पेशावर से लेकर राजधानी इस्लामाबाद में तक महसूस किए गए। हालांकि अभी तक कहीं से भी नुकसान की सूचना नहीं है। अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र में भूकंप के झटके के बाद आज खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के विभिन्न शहरों में झटके महसूस किए गए। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 5.1 थी, जबकि पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (पीएमडी) ने रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 बताई है। यूएसजीएस ने कहा कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के इशकाशिम शहर से 37 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में और 220.7 किलोमीटर की गहराई में था।

खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर खतरा

ओटावा

कनाडा में खालिस्तानी समर्थक (पीकेके) भारतीय समुदाय को लगातार निशाना बना रहे हैं, और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई भारतीय नागरिक अपनी संपत्तियां बेचकर भारत लौटने की योजना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाने से लेकर सीधे भिड़ने, विरोध प्रदर्शन और भारतीयों को धमकाने तक, खालिस्तानी समर्थक अब भारतीयों को हिंसक रूप से उत्पीड़ित कर रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, खालिस्तान के नेतृत्व ने पाकिस्तानी आतंकी समूहों से मिलीभगत के बाद विरोध प्रदर्शनों को और तेज कर दिया है, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां भारतीय नागरिकों की संख्या ज्यादा है। सूत्रों ने बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में हुई एक बैठक के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीयों को धमकाना और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया है। कनाडा में भारतीयों को निशाना बनाने वाले इन खालिस्तानी तत्वों को स्थानीय पुलिस और प्रशासन का समर्थन भी मिल रहा है, जो भारतीय विरोधियों की पहचान और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं।

कनाडा में रह रहे कई भारतीय नागरिक अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। भारतीय रेस्तरां

मालिक, छात्र, और पेशेवर लोग खासतौर पर इन हमलों का शिकार बन रहे हैं। इस माहौल में भारतीयों को धमकी दी जा रही है कि वे खालिस्तान का समर्थन करें या फिर कनाडा छोड़ दें। कुछ समूहों के द्वारा यह चेतावनी दी जा रही है कि भारतीयों को खालिस्तान के पक्ष में झुकने या कनाडा से निकलने के लिए मजबूर किया जाएगा। कनाडा में रह रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अर्पित तिवारी ने कहा, मैं 2017 से कनाडा में रह रहा हूं, लेकिन आज से पहले इस प्रकार का माहौल कभी नहीं देखा। अब भारतीय परिवारों के साथ हिंसक झगड़े हो रहे हैं और लोग अपनी सुरक्षा की खातिर देश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।कनाडा की स्थानीय पुलिस पर भी भारतीयों का भरोसा अब कमजोर हो गया है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी खालिस्तानी समूहों का समर्थन करते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि अगर यह स्थिति यथावत रही तो इस साल के अंत तक भारतीयों के लिए यह माहौल और भी खतरनाक हो सकता है। भारत सरकार इस स्थिति को लेकर गंभीर है और कनाडा सरकार से भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रही है।

नेपाली पीएम ओली के चीन भ्रमण से पहले विदेश मंत्री का बीजिंग जाना तय

काठमांडू

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन भ्रमण से पहले विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा बीजिंग जाएंगी। उनका यह दौरा प्रधानमंत्री ओली की यात्रा का एजेंडा तय करने के लिए होगा। प्रधानमंत्री ओली के 2 दिसंबर से चीन के चार दिनों के भ्रमण पर जाएंगे, जबकि विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा का 30 नवंबर को तीन दिनों की यात्रा पर चीन जाना तय हो गया है।

प्रधानमंत्री ओली 2 दिसंबर से चीन के चार दिनों के भ्रमण पर जाएंगे

विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा का 30 नवंबर को चीन यात्रा पर जाना तय

नेपाल में चीन के राजदूत छन सोंग ने सोमवार को प्रधानमंत्री के चीन भ्रमण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके बाद विदेश मंत्री की बीजिंग यात्रा तय हुई है। विदेश सचिव सेवा लम्साल ने बताया कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर डॉ. आरजू राणा बीजिंग जा रही हैं। लम्साल के मुताबिक 30 नवंबर को बीजिंग पहुंचने वाली विदेश मंत्री 2 दिसंबर से प्रधानमंत्री ओली के प्रतिनिधिमंडल में वहीं से शामिल हो जाएंगी। विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा अपने बीजिंग भ्रमण के दौरान चीन के विदेश मंत्री के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी। इनमें सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख और चीनी संसद के अंतराष्ट्रीय समिति के प्रमुख से मुलाकात प्रमुख है। इसके अलावा डॉ. राणा की मुलाकात चीन के एक्जिम बैंक के प्रमुख और चाइना एड के प्रमुख से भी होने की संभावना है। विदेश मंत्री का यह बीजिंग यात्रा नेपाल में बीआरआई परियोजना के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर की पूर्व तैयारी को लेकर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन की तरफ से नेपाल पर बीआरआई के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। नेपाल ने अपनी तरफ से कुछ शर्तें रखी हैं। अगर चीन ऋण के रूप में नेपाल को आर्थिक अनुदान देता है तो ही बीआरआई को स्वीकार करने की बात नेपाल सरकार की तरफ से कही जा रही है। विदेश मंत्री के चीन भ्रमण का एक और प्रमुख एजेंडा पोखरा में चीन के एक्जिम बैंक के करीब 2600 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान में बदलने का भी है। नेपाल सरकार की तरफ से इसके लिए चीन से औपचारिक रूप से आग्रह भी किया गया है। इस समय चीन इन ऋण पर पांच प्रतिशत का ब्याज भी ले रहा है और इस ऋण को सिर्फ 15 साल में ही वापस करने का समझौता है। नेपाल चाहता है कि यदि चीन इस ऋण को अनुदान में नहीं बदलता है तो कम से कम इसके ब्याज को पांच प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दे।